

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. फिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018—भाद्रपद 23, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक ई-1-15/2018/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 16/2/2016-EO (MM-I) दिनांक 13-07-2018 के तारतम्य में डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (सीजी : 2002), सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को माननीय केन्द्रीय मंत्री, नागर विमानन विभाग (श्री सुरेश प्रभु) की निजी स्थापना में निज सचिव (संचालक स्तर) के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 02-08-2018 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 7-6/2011/32/पार्ट-2.—राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के दामाखेड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव।

राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

जांजगीर, दिनांक 25 अगस्त 2018

क्रमांक 13508/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	करिगांव प.ह.नं. 05	0.016	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया, जिला-रायगढ़।	आमनदुला सब माईनर नं. 2, वितरक नहर निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा		1.426	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रायगढ़	घरघोड़ा	नवापारा		1.719	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				अधिकारी	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रायगढ़	घरघोड़ा	झरियापाली	2.098	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				अधिकारी	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रायगढ़	तमनार	देवगढ़	2.158	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	जरेकेला	1.050	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बासनपाली	2.672	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्रमांक/7008/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	अमलीडीह	1.42	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बालोद.	तरैद से दैहान बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-राईतराई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

क्रमांक 20/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170	0.105
196	0.004
190	0.045

	(1)	(2)
	195/2	0.125
योग	04	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत राईतराई माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 24/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 21/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-राईतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.295 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/1	0.073
28/1	0.093
27/1	0.024
25	0.105
योग	04
	0.295

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत अमलीडीहा माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बासनपाती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.323 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189/1	0.230
187/11	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत रुचिदा माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 25/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-टेका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.678 हेक्टेयर

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रक्वा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

खसरा नम्बर

रक्वा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

207/1,		206/3क	0.061
219/2,	8	214	0.028
262/2		231/12	0.012
196/12, 196/13क	0.024	447/4, 448/1ख	0.057
262/7	0.073	447/1ड़	0.129
262/5	0.036	463/8	0.121
220/3	0.032	465/491/1	0.016
262/6	0.036	464/2	0.032
207/1,		218/1ख	0.028
219/2,	6	206/2	0.008
262/2		212/1	0.113
207/5	0.121	447/2, 448/1क	0.057
262/3	0.026	447/7, 448/2ग	0.024
207/1,		464/1	0.008
219/2,	7	232/3	0.306
262/2		464/491/2	0.008
207/3	0.081	464/7क	0.097
262/4	0.026	233	0.016
योग	12	213/2क	0.065
		219/1	0.004
		231/4	0.028
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत तारापुर माइनर नहर हेतु.		447/1च	0.097
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		464/3	0.073
		464/4	0.020
		442/5	0.121
		442/4क	0.004
		217	0.065
		216	0.041
		447/8, 448/2घ	0.057
		464/5	0.073
		463/2	0.121
		465/2	0.0137
		442/6	0.097

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 26/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)	(1)	(2)
218/1क	0.013	494/1	0.024
योग	34	508/2	0.004
	2.137	510/1	0.012
		523/1	0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव माइनर-2 नहर हेतु।		346/2	0.012
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।		363	0.004
		364/1	0.049
		364/4	0.004
		519/4	0.173
		449/2	0.069
		451/1	0.016
		475/1	0.028
		477/2	0.004
		480/3	0.012
		491/5	0.081
		495/2	0.024
		508/4	0.016
		512/2	0.020
		330/2	0.073
		346/6	0.049
		480/1	0.141
		364/2	0.012
		364/5	0.032
		520/1	0.012
		450/5	0.036
(1) भूमि का वर्णन-		451/2	0.036
(क) जिला-रायगढ़		475/2	0.045
(ख) तहसील-पुसौर		501/6	0.061
(ग) नगर/ग्राम-नावापारा		513/3	0.041
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.390 हेक्टेयर		491/6	0.008
खसरा नम्बर	रक्कमा	508/1	0.053
	(हेक्टेयर में)	508/5	0.012
(1)	(2)	512/4	0.032
		330/3	0.133
330/1	0.073	346/8ख	0.024
331	0.065	496	0.073
364/1ग	0.036	514	0.057
512/1	0.057	365/1	0.061
364/3	0.041	369	0.012
365/2	0.049	450/3	0.049
476	0.045	452/4	0.008
478/1	0.101	475/3	0.032
452/6	0.020	478/2	0.012
477/1क	0.053	480/5	0.008
479	0.012	492	0.004
419/4	0.073	508/8	0.004

(1)	(2)
508/7	0.032
512/5	0.057
योग	60
	2.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अन्तर्गत धनगांव माइनर-1 नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.387 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	योग	रकबा (हेक्टेयर में)
578	0.057	578	0.008
577	0.089	577	0.057
579	0.069	579	0.012
580	0.073	580	0.032
581	0.168	581	0.036
योग	05	578	0.387

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाझर नाला पर पुलिया निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाझर नाला पर पुलिया निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2018

अनुसूची

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-धरमजयगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-खड़गांव
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.338 हेक्टेयर

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-धरमजयगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-सिथरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.193 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/4	0.129
17/5 ख	0.056
20/3	0.008
योग	3
	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग के कि.मी. 16/6 पर पहुंच मार्ग हेतु सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

1288/5	0.161
1281/1	0.032
1288/4	0.097
1288/1	0.040
1280/3	0.008
योग	5
	0.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग के कि.मी. 16/6 पर पहुंच मार्ग हेतु सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 43/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-पुसौर
 (ग) नगर/ग्राम-मल्दा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.361 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अनुसूची
(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन-
4/2	0.057	(क) जिला-रायगढ़
5/5	0.061	(ख) तहसील-पुसौर
8/4	0.008	(ग) नगर/ग्राम-तुरंगा
16/1	0.036	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर
41/3	0.028	
50/4	0.041	
77/1, 91/2	0.161	खसरा नम्बर
4/3	0.016	रकबा
7/2	0.077	(हेक्टेयर में)
9	0.101	(1) (2)
36/1	0.073	2/1 0.105
41/4	0.016	8/3 0.073
51	0.024	
4/4	0.137	
8/2	0.057	
15/1	0.065	
36/3	0.016	
45	0.045	
52/2	0.097	
5/4	0.069	
8/3	0.008	
15/2	0.045	
41/6	0.030	
46/1	0.089	
76	0.004	
योग	25	योग 2 0.178
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के शारा वितरक नहर एवं मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु.		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं तुरंगा माइनर लघु नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
		रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018
		क्रमांक 47/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन-
		(क) जिला-रायगढ़
		(ख) तहसील-पुसौर
		(ग) नगर/ग्राम-बड़े हल्दी
		(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.396 हेक्टेयर
		खसरा नम्बर
		रकबा
		(हेक्टेयर में)
		(1) (2)
		19/3 0.133

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 44/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)	रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018
31/2, 32/1	0.083	
33/15	0.097	
36	0.105	
71/1	0.008	
72/1	0.045	
151/2	0.073	
153/6	0.012	
158/7	0.012	
161/3	0.045	
30/1ख/2	0.020	
19/8	0.076	
31/4, 32/4	0.073	
33/17	0.045	
37/2	0.061	
71/3ख/1	0.012	
73	0.041	
152/1क	0.243	
152/4	0.004	
158/8	0.028	खसरा नम्बर
162/1	0.045	रकबा
21	0.097	(हैक्टेयर में)
32/5	0.081	(1) (2)
35/1, 35/3	0.032	1872 0.041
69/1	0.142	1885 0.049
71/3क	0.004	1873 0.028
74/1	0.029	1875/1 0.049
152/3	0.085	1875/2 0.008
152/8	0.146	1884/1 0.057
160/2	0.041	
165	0.089	योग 6 0.232
30/1ख/1	0.020	
33/16	0.146	
35/2, 35/4	0.032	
70	0.008	
71/3ख/2	0.057	
74/2	0.049	
152/5	0.008	
158/2	0.053	
161/1	0.008	
158/6	0.008	
योग	41	
	2.396	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 48/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुसौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.232 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)
1872	0.041
1885	0.049
1873	0.028
1875/1	0.049
1875/2	0.008
1884/1	0.057
योग	6
	0.232

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं गुडू माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 49/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसार
- (ग) नगर/ग्राम-गुडू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.908 हेक्टेयर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक न के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार मयम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) परा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनसची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हारडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.159 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पार्वति भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित स्प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जाता है) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाएगा। उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
(1)	(2)	अनुसूची
135/6	0.020	
182/4	0.028	
409/25	0.041	
409/27	0.020	
141/7	0.036	
135/7	0.049	(1) भूमि का वर्णन— (क) जिला-बिलासपुर (ख) तहसील-बिल्हा (ग) नगर/ग्राम-खम्हारडीह (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.159 हेक्टेयर
149/2	0.020	
409/29	0.085	
409/17	0.020	
21/1क	0.024	
135/8	0.045	खसरा नम्बर
409/20	0.089	(1) (2)
409/30	0.061	
409/19	0.028	14 0.024
21/4	0.024	17 0.057
135/2	0.121	18/1 0.028
409/28	0.028	18/3 0.032
409/31	0.109	13/1 0.036
182/3	0.024	13/2 0.020
409/14	0.036	19/3 0.020
योग	20	20 0.178
		88/2 0.061
		63/1 0.045
		63/2 0.045
		64 0.045
		65/1 0.004
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं गुदू माइनर नहर निर्माण हेतु।	77/1, 78/1 0.020	
3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।	80 0.032	
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शम्मी अबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।	77/2, 78/2 0.105	
	81/1 0.052	
	83/2 0.012	
	81/2 0.052	

(1)	(2)	(1)	(2)
82, 83/1	0.109	250/1	0.032
57/1	0.004	8/2	0.032
57/4	0.004	12	0.012
94/4	0.012	8/1	0.113
86, 88/1	0.073	7/2	0.045
92	0.089	7/7	0.049
योग	29	7/5	0.008
	1.159	152/2	0.024
		7/4	0.008
		10/1	0.073
		27/1	0.061
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के खम्हारडीह माइनर नहर निर्माण हेतु।		27/2	0.008
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है।		28/1	0.032
		28/2	0.024
		29	0.053
		30/3	0.032
		34/1	0.024
		34/2	0.057
		30/2	0.061
		32	0.053
		33/1,	0.142
		33/2	
		41/1	0.020
		43/1	0.053
		43/2	0.105
		61/2	0.020
		62	0.073
		65/5	0.040
		65/6	0.032
		75	0.053
		86	0.020
		82	0.016
(1) भूमि का वर्णन-		81	0.016
(क) जिला-बिलासपुर		80	0.081
(ख) तहसील-तखतपुर		76/1	0.049
(ग) नगर/ग्राम-मोछ		76/2	0.049
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.283 हेक्टेयर		153/1	0.024
		144/3	0.045
खसरा नम्बर	रकबा	145/2	0.028
	(हेक्टेयर में)	154/4	0.028
(1)	(2)	153/4	0.065
5	0.117	152/1	0.032
7/6	0.073	146/3	0.129
30/1	0.016	147	0.045
7/1	0.012	148	0.024
10/2	0.057	149	0.036
258/2	0.388	412	0.045
		413	0.259

(1)	(2)	(1)	(2)
411/7	0.089	1441	0.166
411/8	0.077	650/1	0.999
587/4	0.012	1436/4	0.409
648	0.028	29	0.053
647/1	0.012	30/3	0.032
647/2	0.012		
647/3	0.012	योग	107
647/4	0.012		8.283
646/1	0.016	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार	
646/2	0.024	बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.	
646/3	0.016	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
636	0.028	(राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
637	0.008		
638/1	0.040		
638/2	0.036		
638/3	0.012		
633	0.040		
631	0.045		
597/3	0.012		
630/1	0.040	क्रमांक 04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
607	0.020		
604	0.032		
606	0.024		
605	0.049		
582	0.053		
579	0.053		
586	0.065		
584/1	0.020		
583	0.081		
584/2	0.073	(1) भूमि का वर्णन—	
493	0.097	(क) जिला-बिलासपुर	
491/2	0.032	(ख) तहसील-बिल्हा	
764/1	0.413	(ग) नगर/ग्राम-पेण्डीडीह	
831/1	0.053	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.790 हेक्टेयर	
831/2	0.065		
832/1	0.077		
832/2	0.081		
841/2	0.109		
1314/6	0.121		
1314/5	0.243	127/1	0.097
1314/3	0.194	127/2	0.016
1314/9	0.202	133/1	0.089
1314/7	0.311	134	0.040
1315/2	0.138	153/1	0.004
1436/2	0.057	152	0.057
1437/3	0.214	162	0.081
1437/4	0.121	160/1	0.004

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-पेण्डीडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.790 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(1)	(2)	(1)	(2)
161	0.057	85/1	0.040
160/2	0.036	85/2	0.008
151	0.049	85/3	0.021
166/2	0.057	84/1	0.016
167	0.073	95/1	0.032
114	0.008	95/5	0.081
113/3	0.053	95/8	0.032
115/2	0.057	95/18	0.012
113/2	0.012	95/15	0.008
योग	17	0.790	95/20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है।

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-ऐटुलकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.309 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रक्कबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

79/1

0.024

87/1

0.028

86

0.056

योग 36 1.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अमेरीकापा माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है।

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

(1) (2)

क्रमांक 11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-अमेरी अकबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.239 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रक्कम
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

49/3

0.036

49/4

0.024

48

0.028

52/2

0.045

50/1

0.004

52/1

0.057

52/3

0.016

52/4

0.012

38/2

0.008

54

0.057

60/1

0.061

60/2

0.049

60/3

0.068

61/1

0.008

61/2

0.089

63

0.077

62/2

0.008

64/2

0.032

64/3

0.032

64/4

0.020

64/5

0.016

69

0.065

68/1

0.045

71

0.057

73

0.053

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक 15/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची	(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-	164/3,	
(क) जिला-बिलासपुर	164/4	0.073
(ख) तहसील-बिल्हा	165	0.121
(ग) नगर/ग्राम-उड़नताल	163/1	0.052
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.972 हेक्टेयर	163/7 3	0.024 0.089
खसरा नम्बर	रकबा	4/1
	(हेक्टेयर में)	37/3
(1)	(2)	37/7 38/3
10/2	0.012	31
129/1	0.267	38/2
129/2	0.134	38/1
130/4	0.004	43/4, 43/6
130/1	0.016	43/5
128/1	0.154	58/1
128/2	0.316	68/1
133/1	0.117	57/13
133/2	0.057	57/10, 57/11
4/2	0.016	
164/1,	0.073	
164/2		योग 42
164/10	0.097	2.972
164/8	0.016	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार
163/3	0.068	बैराज परियोजना के दण्डों माइनर नहर निर्माण हेतु.
163/6	0.032	
163/4	0.202	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
163/2	0.008	(राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.
43/10	0.073	
27/1,		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
27/2	0.170	पी. द्यानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

प्रारूप-ख

[नियम 5(1) देखिये]

क्रमांक 114/बी 121/2017-18.—राज्य सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.न., तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.न.-40, तहसील-पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है।

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 33, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छ.ग. भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप से आपेक्ष भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)	
			खसरा नं. (4)	रकबा (5)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली/33	173/3	0.085
योग कुल ख. नं. 1				0.085

टीप :—

- भूमि के नीचे लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है।

बी. पी. जायसवाल,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th August 2018

No. 857/Confld./2018/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) until further orders ;—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
2.	Smt. Neeta Yadav, Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Janjir-Champa.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.